

सागर संभाग में चयनित सार्वजनिक एवम् निजी बैंकों की गैर निष्पादित सम्पत्ति का अध्ययन

फरहा नाज* डॉ. प्रभा अग्रवाल**

* शोधार्थी (वाणिज्य) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (वाणिज्य) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह अध्ययन मध्य प्रदेश के सागर संभाग में संचालित चुनिंदा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की प्रवृत्तियों, कारणों और प्रभावों की विश्लेषणात्मक जांच प्रस्तुत करता है। पांच साल की अवधि में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों डेटा स्रोतों का उपयोग करके, अनुसंधान विभिन्न बैंकिंग संस्थानों में एनपीए की मात्रा और पैटर्न की तुलना करता है। अध्ययन एनपीए के संचय में योगदान देने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों की भी पड़ताल करता है, जिसमें ऋण वितरण प्रथाएं, उधारकर्ता चूक, आर्थिक स्थिति और नियामक उपाय शामिल हैं। तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए का बोझ अधिक है, यह अध्ययन भारतीय बैंकिंग प्रणाली के भीतर वित्तीय स्वास्थ्य और ऋण दक्षता में सुधार से संबंधित नीति निर्माताओं, बैंकिंग पेशेवरों और शिक्षाविदों के लिए महत्वपूर्ण है।

शब्द कुंजी – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सागर डिवीजन, परिसंपत्ति गुणवत्ता, सकल एनपीए अनुपात, वित्तीय प्रदर्शन, ऋण वसूली, ऋण जोखिम, बैंकिंग क्षेत्र सुधार।

प्रस्तावना – भारतीय बैंकिंग देश और उसके लोगों की जीवन रेखा है। बैंकिंग ने अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विकसित करने और भारतीय क्षितिज पर प्रगति की एक नई सुबह लाने में मदद की है। इस क्षेत्र ने लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को हकीकत में बदला है। लेकिन ऐसा करने के लिए, उसे मीलों दूर तक कठिन भूभाग पर नियंत्रण करना पड़ा है। आज भारतीय बैंक आत्मविश्वास के साथ दुनिया के आधुनिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में से एक है। इसे अर्थव्यवस्था की सफलता या विफलता के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक माना जाता है। बैंक भी अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने वित्तीय संस्थानों में से एक है। वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जमा राशि जुटाने और ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकिंग प्रणाली ईंधन इंजेक्शन प्रणाली है जो बचत जुटाकर और उन्हें उच्च रिटर्न निवेश के लिए आवंटित करके आर्थिक दक्षता को उत्तेजित करती है। आधुनिक वाणिज्यिक बैंकिंग वाला देश, अपने वर्तमान स्वरूप में, हाल ही में उत्पन्न हुआ है।

भूमिका – भारत के मध्य भू-भाग पर विद्यमान मध्यप्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सागर संभाग अवस्थित है। जिसके अन्तर्गत, सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले शामिल हैं, जो मिलकर एक संभाग का रूप देते हैं। इस संभाग का निर्माण दमोह एवं सागर जिलों को जबलपुर संभाग से पृथक कर निर्मित किया गया था। तत्पश्चात 26 जनवरी 1973 को पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर को रीवा संभाग के जिलों से पृथक कर इस संभाग में मिला लिया गया था। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ के निवाड़ी तहसील को अलग कर जिले के रूप में स्थापित किया गया। निवाड़ी जिले को मिला

कर वर्तमान समय में सागर संभाग में समाहित जिलों की संख्या छः है। संभाग के अन्तर्गत सभी जिलों को संस्कृति, भाषायी विशिष्टता एवं पर्यटन से प्रदेश में इस संभाग की एक अलग ही पहचान है जिले के सागर संभाग के नाम से सम्बोधित किया जाता है।

ऐतिहासिक स्थिति – भारत के मध्य भाग में स्थित सागर संभाग में सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सहित कई जिले शामिल हैं। क्षेत्र का बैंकिंग क्षेत्र व्यक्तियों, व्यवसायों और कृषि उद्यमों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के बैंक इस संभाग में काम करते हैं, जो ग्रामीण और शहरी आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जैसे निजी बैंकों के साथ-साथ मजबूत उपस्थिति है। सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) भी लघु उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों और हाशिए के समुदायों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। सागर संभाग में बैंकिंग क्षेत्र कृषि निर्भरता, औद्योगीकरण और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रथाओं जैसे कारकों से काफी प्रभावित है। इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं और माइक्रोफाइनेंस पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन प्रयासों में वृद्धि देखी गई है। इन विकासों के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें बुनियादी ढाँचे की कमी, कम वित्तीय साक्षरता और दूरदराज के इलाकों में पहुँच संबंधी समस्याएँ शामिल हैं। डिजिटल बैंकिंग की भूमिका बढ़ गई है, और ग्राहकों की बढ़ती संख्या मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)

सेवाओं को अपना रही है।

आर्थिक विकास में बैंकिंग की भूमिका – सागर संभाग में बैंकिंग क्षेत्र बचत को जुटाकर और उन्हें उत्पादक निवेशों में लगाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और कृषि सावधि ऋण जैसी योजनाओं के तहत किसानों को बड़े प्रतिशत ऋण दिए जाते हैं। इसके अलावा, छोटे और मध्यम उद्यम (एसएमई) और कुटीर उद्योग अपने परिचालन का विस्तार करने, रोजगार सृजित करने और क्षेत्रीय आय के स्तर में सुधार करने के लिए बैंक वित्तापोषण पर निर्भर हैं। कृषि और व्यवसाय ऋण के अलावा, बैंक किफायती ऋण देकर आवास और शिक्षा क्षेत्र में भी योगदान करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और शिक्षा ऋण सब्सिडी जैसी विभिन्न सरकार समर्थित पहलों की शुरुआत ने वित्तीय संस्थानों को अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) और ऋण वसूली के रुझान – सागर संभाग में कार्यरत बैंकों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनकर उभरी हैं। एनपीए ऐसे ऋण या अग्रिम हैं जिनमें उधारकर्ता 90 दिनों या उससे अधिक समय तक ब्याज या मूलधन का भुगतान करने में विफल रहता है। एनपीए का बढ़ता स्तर बैंकों की लाभप्रदता और तरलता को प्रभावित करता है, जिससे ऋण प्रवाह में समग्र मंदी आती है। पिछले दशक में, क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में उच्च एनपीए अनुपात का सामना करना पड़ा है, जैसे कि ऋण देने के मानदंडों में ढील, कृषि ऋण चूक और अपर्याप्त जोखिम मूल्यांकन तंत्र जैसे कारक। सागर संभाग में एनपीए में प्राथमिक योगदानकर्ताओं में कृषि क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई), और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सरकारी नीतियां और सिफारिशें – सरकार ने सागर संभाग में एनपीए की समस्या को दूर करने और बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई नीतियां और योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना और माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) जैसी पहलों ने छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण पहुंच में सुधार करने और वित्तीय संकट को कम करने में मदद की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों के बीच बेहतर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियामक मानदंड लागू किए हैं। सागर संभाग में बैंकिंग दक्षता बढ़ाने के लिए, यह अनुशंसा की जाती है कि बैंक एनपीए प्रबंधन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाएं। क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मजबूत करना, उन्नत जोखिम प्रबंधन तकनीकों को लागू करना और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ऋण चूक को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त, बैंकों और स्थानीय सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग ऋण वसूली दरों में सुधार कर सकता है और वित्तीय समावेशन प्रयासों को सुव्यवस्थित कर सकता है। बैंकिंग पहुंच बढ़ाने और परिचालन लागत को कम करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग की पहुंच को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

सागर जिले की भौगोलिक स्थिति एवं नाम की उत्पत्ति से सम्बंधित लोककथा – भारत के मध्य में मध्यप्रदेश व मध्यप्रदेश के मध्य में सागर

जिला अर्थात् मध्यप्रदेश का हृदय स्थल सागर स्थित है, जो 23°10' से 24°27' उत्तरी अक्षांश तथा 78°52' से 79°21' पूर्वी देशांश के मध्य फैला है। सागर जिले का क्षेत्रफल 10,252 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 23,78,458 के लगभग है तथा लिंगानुपात 896 है। सागर जिले की बारह तहसीलें – बीना, खुरई, मालथौन, बंडा, शाहगढ़, राहतगढ़, जैसीनगर, सागर, गढ़ाकोटा, रहली, देवरी तथा केसली है।

भौगोलिक स्थिति: सागर जिला मध्यप्रदेश के उत्तर मध्य में स्थित है। यह क्षेत्र प्रायशः बुंदेलखण्ड के नाम से जाना जाता है। सागर के उत्तर में छतरपुर और ललितपुर जिले, पश्चिम में विदिशा, गुना जिले, दक्षिण में नरसिंहपुर, पश्चिम – दक्षिण में रायसेन तथा पूर्व में दमोह जिले की सीमायें मिलती हैं।

सागर शहर के बीचों-बीच एक अत्यंत सुन्दर झील है जिसे लाखवा बंजारा झील के नाम से जाना जाता है। ऐसी लोक किवंदंती है कि सागर झील का निर्माण 13वीं शताब्दी में बंजारों ने किया था। इसका निर्माण लाखवा बंजारा नामक बंजारे द्वारा कराया गया था। लाखवा एक प्रसिद्ध बंजारा था, जो अपने अन्य बंजारा साथियों के साथ लड्डू भैंसों, बैलों पर नमक और अन्य ग्राहस्थिक सामग्री लादकर बुंदेलखण्ड क्षेत्र में आते थे और घूम-घूम कर व्यापार किया करते थे। लड्डू भैंसियों के साथ अत्यधिक जल की आवश्यकता पड़ती थी।

अतः जहाँ पर पानी कम या उपलब्ध नहीं होता था, वहाँ बंजारे अपने निजी पैसे से तालाब, बावड़ियों का निर्माण करा देते थे। भैंसियों की जल आपूर्ति के लिए बंजारों ने दो पहाड़ियों के मध्य सागर शहर में विशाल तालाब का निर्माण करवा दिया और बाद में इसी सागर झील के नाम से दांगियों, अहीरों एवं गौड़ शासकों ने शासन किया।

पर्वत एवं नदियाँ : सागर जिला मालवा पठार के दक्षिण – पूर्व किनारे विंध्यांचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। यहाँ सामान्य तल के ऊपर तीन सौ से पांच सौ फुट ऊँची उठी हुई पर्वत मालाएं, ऊपर उल्लिखित नदी पत्रों को एक-दूसरे से प्रथक करती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख पर्वतमाला लिधोरा से बंडा होते हुए जयसिंहनगर तक दक्षिण-पश्चिम की ओर फैली है। ये पहाड़ियां, जिनके शिखर सपाट हैं, अधिकांशतः वनाच्छादित हैं और कहीं-कहीं उनकी ऊंचाई लगभग 2000 फुट है। पथरिया जो सागर से निकट है, इसकी ऊंचाई औसत समुद्रतल से 2,035 फुट है। आगे चलकर तेंदू डाबर जो 2,182 फुट ऊँची है।

जलवायु एवं तापमान: किसी क्षेत्र की जलवायु उस क्षेत्र के वातावरण का महत्वपूर्ण घटक होती है अर्थात् जलवायु वन, वर्षा, मिट्टी एवं कृषि को प्रभावित करने वाला तत्व है। सागर में और जिलों की अपेक्षा गर्मी कम पड़ती है। इसलिए यहाँ का रहवास निरोग और सुखद है।

नवम्बर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है, इसके पश्चात् मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है तथा वर्षा मध्य जून से प्रारंभ होकर सितम्बर के अंत तक होती है। अक्टूबर में वर्षा ऋतु, शीत ऋतु में परिवर्तित होने लगती है। सागर जिले का न्यूनतम तापमान जनवरी माह में 05° सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 47° सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है। सागर जिले की औसत वर्षा लगभग 45 इंच है।

जंगली जानवर: सागर जिले में हिरण, चीतल, सांभर, नीलगाय, काला हिरण, सोनकुत्ते, सियार, भालू, बारहसिंगा, लोमड़ी, सेई, बन्दर, चौसिंघा, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, आदि जानवर पाये जाते हैं। खनिज सम्पदा: सागर जिले में विपुल खनिज सम्पदा नहीं है तथापि इस जिले में वृहद मात्रा

में निर्माण सामग्री उपलब्ध है और चूना पत्थर भी अनेकों स्थानों पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। मालथौन के उत्तार में अटा में बलुआ पत्थर पट्टीनुमा परतों के रूप में पाया जाता है।

उद्देश्य:

1. आर्थिक विकास में बैंकिंग की भूमिका पर अध्ययन करना।
2. बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए सरकारी नीतियों और सिफारिशों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पना:

- चयनित सार्वजनिक एवं निजी बैंकों की गैर निष्पादित सम्पत्ति में अंतर है।

अनुसंधान क्रियाविधि- इस शोध में एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और उनकी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। अध्ययन का उद्देश्य सागर संभाग के चयनित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित सम्पत्तियों (एन.पी.ए.) की स्थिति का तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक आकलन करना है। द्वितीय समकों एवं सूचनाओं का संग्रहण हेतु पुस्तकालयों में उपलब्ध शासकीय एवं अर्धशासकीय प्रकाशन तथा निजी प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित सामग्री, पत्र-पत्रिकाएँ, समाचार पत्रों आदि से उपयोग किया गया है, इसके अलावा इंटरनेट का भी सहारा लिया गया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय बैंकर्स, संभागीय एवं जिलेवार समितियों एवं अग्रणी भारतीय स्टेट बैंक टीकमगढ़ से संमक संग्रहित किये गये हैं।

शोध का क्षेत्र एवं सीमाएँ:- शोध अध्ययन का क्षेत्र मध्यप्रदेश के सागर संभाग से संबंधित है जिसमें बैंकों की संख्या अत्याधिक होने के कारण सार्वजनिक एवं निजी बैंकों का चयन दैवनिर्दर्शन पद्धति द्वारा किया गया है जिसमें पाँच सार्वजनिक एवं निजी बैंकों का चयन किया है जो निम्न प्रकार है।

चयनित बैंक

सार्वजनिक बैंक

1. एसबीआई बैंक
2. इंडियन बैंक
3. पीएनबी बैंक
4. बीओआई बैंक
5. केनरा बैंक

चयनित निजी बैंक

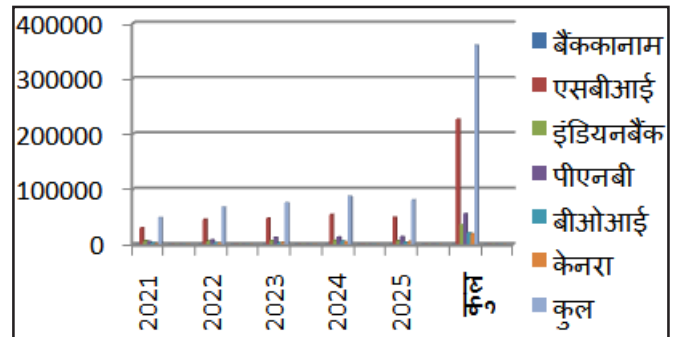
1. आईसीआईआई बैंक
2. एक्सिस बैंक
3. एचडीएफसी बैंक
4. बंधन बैंक
5. एयू स्मॉल फिन. बैंक

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 1 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सकल एनपीए का पाँच वर्षों (2021-2025) का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्पष्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का एनपीए राशि के मामले में सर्वाधिक है, जो 2021 में 30,401 रुपये लाख से बढ़कर 2024 में 54,061 रुपये लाख तक पहुँचा और 2025 में थोड़ा घटकर 49,017 रुपये लाख रहा। यह कुल सार्वजनिक क्षेत्र के एनपीए का लगभग 63% हिस्सा है, जो बैंकिंग प्रणाली में SBI की प्रमुखता और उसके जोखिम दोनों को दर्शाता है। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का भी योगदान उल्लेखनीय है, जिसका एनपीए 2021 के 6,024 रुपये लाख से लगातार बढ़कर 2025 में 14,647 रुपये लाख तक पहुँच गया, जिससे इसका कुल हिस्सा 15-6% हो गया। इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा क्रमशः 9-97% और 5-94% रहा। केनरा बैंक का योगदान सबसे कम (5-50%) रहा, लेकिन इसमें भी वृद्धि का

रुझान देखा गया। समग्र रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए 2021 के 48,810 रुपये लाख से बढ़कर 2024 में 87,254 रुपये लाख तक पहुँचा और 2025 में 80,842 रुपये लाख पर आकर स्थिर हुआ। यह दर्शाता है कि कुछ सुधारात्मक कदम 2025 में प्रभावी हुए, जिससे गिरावट आई। परंतु कुल मिलाकर यह प्रवृत्ति बैंकों की ऋण प्रबंधन प्रणाली में कमियों और बढ़ते जोखिम को इंगित करती है।

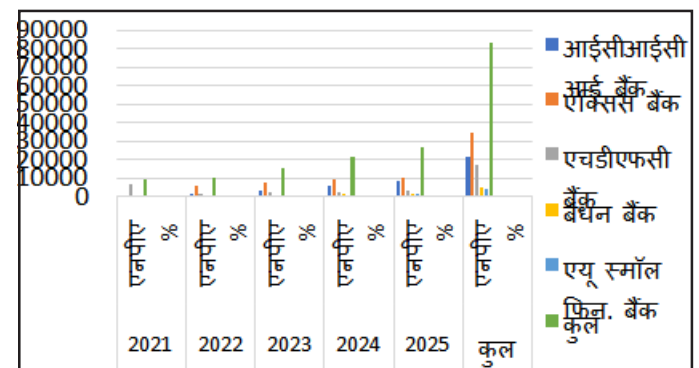
ग्राफ 1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एनपीए (लाख रुपये)



तालिका 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

तालिका 2 में निजी क्षेत्र के बैंकों के सकल एनपीए का पाँच वर्षों (2021-2025) का विवरण दिया गया है। इसमें स्पष्ट है कि एक्सिस बैंक और आईसीआईआई बैंक सबसे अधिक प्रभावित रहे। एक्सिस बैंक का एनपीए 2021 में केवल 809 रुपये लाख था, लेकिन 2022 में यह तेजी से बढ़कर 5,722 रुपये लाख और 2025 में 10,595 रुपये लाख हो गया। कुल एनपीए में इसका हिस्सा 41.94% रहा, जो निजी क्षेत्र में सर्वाधिक है। आईसीआईआई बैंक का एनपीए भी उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 2021 के 993 रुपये लाख से बढ़कर 2025 में 8,713 रुपये लाख पहुँच गया और इसका हिस्सा 25-87% रहा। एचडीएफसी बैंक, जो आमतौर पर स्थिर माना जाता है, 2021 में 7,095 रुपये लाख के उच्च स्तर पर था लेकिन अगले वर्षों में अपेक्षाकृत संतुलित रहा और 2025 तक 3,378 रुपये लाख पर सीमित रहा। यह दर्शाता है कि बैंक ने प्रभावी रिकवरी रणनीतियाँ अपनाई। बंधन बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का कुल एनपीए योगदान क्रमशः 5-97% और 5-41% रहा, जो छोटे स्तर के जोखिम को दिखाता है। समग्र रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों का कुल एनपीए 2021 के 9,484 रुपये लाख से बढ़कर 2025 में 26,412 रुपये लाख तक पहुँच गया। यह प्रवृत्ति संकेत देती है कि निजी बैंकों में ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर दबाव बढ़ा है, विशेष रूप से तेजी से विस्तार करने वाले बैंकों में।

ग्राफ 2: निजी क्षेत्र के बैंक एनपीए (लाख रुपये)



निष्कर्ष – सागर संभाग के चयनित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की गैर निष्पादित संपत्तियों (NPA) का विश्लेषण करने के उपरांत यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर निष्पादित संपत्तियों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। अतः स्पष्ट होता है कि चयनित सार्वजनिक एवं निजी बैंकों की गैर निष्पादित सम्पत्ति में अंतर है इसका प्रमुख कारण प्राथमिकता क्षेत्र में अधिक ऋण वितरण, कमजोर ऋण वसूली तंत्र, और प्रशासनिक अक्षमता है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र के बैंक अपने बेहतर जोखिम प्रबंधन, कुशल ऋण मूल्यांकन प्रणाली तथा तकनीकी हस्तक्षेप के कारण एनपीए पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण रखने में सफल रहे हैं। यह भी दर्शाता है कि गैर निष्पादित संपत्तियाँ न केवल बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करती हैं, बल्कि समग्र बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता और आर्थिक स्थायित्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। अतः यह आवश्यक है कि बैंकों द्वारा कठोर ऋण स्वीकृति मानदंडों को अपनाया जाए, समय पर पुनरुद्धार उपाय किए जाएं, और वसूली तंत्र को अधिक सशक्त किया जाए। इसके अतिरिक्त, नीति-निर्माताओं को भी चाहिए कि वे एकीकृत नियामक ढांचे के माध्यम से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के बैंकों को सहयोग प्रदान करें, जिससे वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिले और एनपीए की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके। इस प्रकार, यह अधन नीति एवं व्यावहारिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, बी.के., बुन्देलखण्ड का इतिहास (1531 से 1857 ई. तक), डी. के. प्रिंटवर्ल्ड प्रा. लि., नई दिल्ली, 2019, पृ. 12
2. तिवारी, गोरेलाल, बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 1990, पृ. 1
3. त्रिपाठी, काशीप्रसाद, बुन्देलखंड का सामाजिक-आर्थिक इतिहास, समय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020, पृ. 13
4. गुप्त, नर्मदा प्रसाद, बुन्देलखण्ड का सीमांकन, कृष्णदत्त बाजपेयी (सं.), बुन्देलखण्ड - गौरव खण्ड-1, महेंद्र कुमार मानव अभिनन्दन समिति, भोपाल, 1993, पृ. 211-212
5. जोशी, मदनमोहन (सं.), मध्यप्रदेश सन्दर्भ, दैनिक नईदुनिया प्रकाशन, 1998-99, पृ. 16
6. रैकवार, महेश कुमार, सागर संभाग में इसाई मिशनरियों की गतिविधियाँ प्रोटेस्टेंट मत के विशेष सन्दर्भ में (1878 से वर्तमान तक), शोध प्रबन्ध, इतिहास विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, 2013, पृ. 1
7. जिला प्रशासन निवाड़ी, दिनांक 01.01.2023 को उद्घृत <https://niwari.nic.in/>
8. डेंगरे, एकता, बुंदेलखंड के अवनद्ध वाघों की बजौटी वादन शैली, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2013, पृ. 1
9. जैन, किरण, सागर जिला और उद्योग-धन्धे, लक्ष्मी पाण्डेय (सं.), ये है बुंदेलखंड भाग - 1,
10. अनुज्ञा बुक्स पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2020, पृ. 145
11. जिला प्रशासन सागर, दिनांक - 23.01.2023 को उद्घृत <http://sagar.nic.in/>
12. वही
13. त्रिपाठी, काशीप्रसाद, बुंदेलखंड के तालाबों एवं जल प्रबंधन का इतिहास, बुन्देलखण्ड अनुसंधान पोर्टल, दिनांक - 30.01.2023 को उद्घृत <https://cutt.ly/NwAsJuSd>
14. कृष्णन, व. सु., मध्यप्रदेश जिला गजेटियर सागर, भोपाल, 1970, म.प्र., पृ. 4
15. वही, पृ. 5
16. रायबहादुर, हीरालाल, सागर- सरोज, सागर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (हिन्दी), 1922, पृ. 4
17. रायकवार, माधवसिंह, टीकमगढ़ जिले के मंदिर एवं स्थापत्य कला, नागेश दुबे एवं मोहन लाल चट्टार (सं.), मध्य भारत की कला, संस्कृति एवं पुरातत्व, एस. एस. डी. एन. पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृ. 46
18. सोनी, नारायण दास, ऐतिहासिक ओरछा राज्य से बना जिला टीकमगढ़, ये है बुंदेलखण्ड भाग - 2, पूर्वोक्त, पृ. 67
19. पाण्डेय, लक्ष्मी, निवाड़ी परिचय, ये है बुंदेलखण्ड भाग - 2, वही, पृ. 63
20. जिला प्रशासन निवाड़ी, पूर्वोक्त
21. तिवारी, शिव कुमार, मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में सेवा केन्द्र का भौगोलिक विश्लेषण, शोध प्रबंधा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झाँसी, 1996, पृ. 32
22. श्रीवास्तव, रूचि, जिला टीकमगढ़ में कृषिगत भूमि- उपयोग एवं पोषण स्तर, शोध प्रबंध,
23. बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी, 2001, पृ. 17
24. टीकमगढ़ विकास योजना, संचनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर
25. निवेश अधिनियम, 1973 के प्रवाधानान्तर्गत प्रकाशित मध्यप्रदेश भोपाल, पृ. 2
26. सैनी, कल्पना एवं चौबे, रमेश, सागर की सांस्कृतिक विरासत, आदित्य पब्लिशर्स, बीना,
27. सागर, म.प्र., 2007, पृ. 77

तालिका 1: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एनपीए (लाख रुपये)

	2021		2022		2023		2024		2025		कुल	
बैंक का नाम	एनपीए	%	एनपीए	%	एनपीए	%	एनपीए	%	एनपीए	%	एनपीए	%
एसबीआई	30401	8.45%	45460	12.63	47726	13.26	54061	15.02	49017	13.62	226665	63.0%
इंडियन बैंक	6905	1.90%	6685	1.85	7508	2.08	7792	2.16	6997	1.94	35887	9.97%
पीएनबी	6024	1.67%	8731	2.42	12740	3.54	13991	3.88	14647	4.07	56133	15.6%
बीओआई	3546	0.98%	3519	0.97	3485	0.96	6159	1.71	4657	1.29	21366	5.94%
केनरा	1934	0.54%	3037	0.84	4062	1.12	5251	1.45	5524	1.53	19808	5.50%
कुल	48,810	13.56%	67,432	18.74	75,521	21%	87,254	24.25	80,842	22.46	359859	100%

स्रोत - अग्रणी भारतीय स्टेट बैंक, टीकमगढ़।

नोट- वर्ष 2021 में निवाड़ी जिले के उपलब्ध तालिका से संबंधित आँकड़े नहीं हैं। (कोविड- 19 महामारी के कारण)

तालिका 2 : निजी क्षेत्र के बैंक एनपीए (लाख रुपये)

	2021		2022		2023		2024		2025		कुल	
बैंक का नाम	एनपीए	%	एनपीए	%	एनपीए	%	एनपीए	%	एनपीए	%	एनपीए	%
आईसीआई सीआई बैंक	993	1.20	1534	1.85	3672	4.44	6473	7.83	8713	10.54	21385	25.87
एक्सिस बैंक	809	0.97	5722	7.92	7668	9.27	9881	11.95	10595	12.81	34675	41.94
एचडीएफसी बैंक	7095	8.58	1447	1.75	2497	3.02	2776	3.35	3378	4.08	17193	20.79
बंधन बैंक	0	0	777	0.93	1040	1.25	1317	1.59	1798	2.17	4932	5.97
एयू स्मॉल फिन. बैंक	587	0.71	568	0.68	423	0.51	969	1.17	1928	2.33	4475	5.41
कुल	9484	11.47	10048	12.15	15300	18.50	21416	25.90	26412	31.95	82660	100

स्रोत - अग्रणी भारतीय स्टेट बैंक, टीकमगढ़।

नोट - वर्ष 2021 में निवाड़ी जिले के उपलब्ध तालिका से संबंधित आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। (कोविड- 19 महामारी के कारण)
